Class: B.Com II
Subject - MFI
Paper - IV (S)
Topic - SIDCs
Lecture - 15
By Dr. C P Sahu
Marwari College Darbhanga.

राज्य औद्योगिक विकास निगमें (1)

राज्य औद्योगिक विकास निगम (State Industrial Development Corporation - SIDCs) पूर्णरूप से राज्य सरकारों के संस्थान है। इसकी स्थापना 1960 में राज्य सरकारों द्वारा लघु उद्योगों के विकास के लिए की गयी। विभिन्न राज्यों में राज्य वित्त निगम निगमों के स्थापना के बाद राज्य औद्योगिक विकास निगम का शुरुआत किया। तत्काल इस समय भारत में 26 निगमें कार्य कर रहे हैं।

निगम के कार्य एवं उद्देश्य :- निम्नलिखित हैं —

1. औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना जैसे - विद्युत प्लान्ट, भवन, मशीन, कच्चामाल इत्यादि
2. औद्योगिक उपक्रमों का प्रवर्तन एवं प्रबन्ध करना
3. नवीन उद्योगों की स्थापना की सुविधा खोजना
4. क्षेत्र विशेष में तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करना
5. सरकारी एवं निजी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
6. औद्योगिक बस्तियों का स्थापना करना

संगठन एवं प्रबन्ध - इनके प्रबंध के लिए संचालक मंडलों की नियुक्ति की गयी है जिसमें संचालक राज्य सरकार द्वारा नामांकित होते हैं। लेकिन राज्यों में सरकार के अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थाओं से भी संचालकों की नियुक्ति की जाती है।

निगमों की तरह राज्य औद्योगिक विकास निगमों के वित्तीय स्रोतों में प्रदत्त पूंजी संचय कोष, सरकार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण, जनता की जमा और बॉण्ड एवं ऋणपत्रों का निर्गमन प्रमुख है। इसके अलावा ये निगम सरकार से अनुदान तथा अन्य प्रोत्साहन राशियाँ भी प्राप्त करते हैं।

वित्तीय सहायता के रूप (A) राज्य के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के औद्योगिक उपक्रमों के द्वारा निर्गमित अंश

(B) उपक्रमों द्वारा निर्गमित पूँजी का अभिगोपन करना

(C) राज्य के औद्योगिक उपक्रमों को प्रत्यक्ष कृषि देना

(D) अन्य संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं स्थगित भुगतानों की गारंटी देना।

(1) वित्तीय सहायता (Financial Assistance) :- राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा स्वीकृत ऋणों की राशि में तेजी से वृद्धि हुई है।

करोड़ रुपये में

वर्ष	स्वीकृत	वितरण
1965-66	1.7	1.4
1970-71	19.3	11.0
1975-76	37.0	26.4
1980-81	216.4	124.6
1984-85	477.9	297.6
1990-91	815.0	591.4
2000-01	2080.3	1664.1
2001-02	1593.5	1418.

Scanned with CamScanner

इसप्रकार राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा स्थापना से लेकर मार्च 2002 तक 22,836 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की गयी और उसमें से 8,317 करोड़ रुपये वितरित किये गये।

(2) बीज पूँजी योजना - (Seed Capital Plan) यह योजना IDBI के द्वारा 1976 से प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य ऐसे नये साहसियों को पूँजी प्रदान करना जो तकनीकी रूप से प्रशिक्षित हैं तथा व्यावसायिक योग्यता रखता है।

राज्य औद्योगिक विकास निगमों के कार्यकलापों की समीक्षा करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निगम अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य कर रहे हैं तथा इनके द्वारा राज्यों के संतुलित औद्योगिक विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिला है।

Scanned with CamScanner

कहीं कहीं ये निगम राज्य वित्त निगमों के क्षेत्र में भी अपनी भागीदारी दे रहे हैं विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण प्रदान करने में। यही में इन निगमों का प्राथमिक उद्देश्य उपक्रमों का प्रवर्तन एवं विकास करना है और उस दिशा में अपनी पूर्ण रूप से ताकत लगाना है। (4)

(3) उद्देश्यवार सहायता - (Purposewise Assistance)

राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्वीकृत सहायता के उद्देश्यवार स्वरूप में पूर्व के वर्ष के तुलना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। कुल सहायता राशि का तीन-चौथाई भाग नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होता रहा।

(4) उद्योगवार सहायता - (Industrywise Assistance)

राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा स्वीकृत कुल सहायता का 50% से अधिक भाग उन उद्योगों में लगाया जिनमें वस्त्र, विविध रासायनिक, मशीनरी सेवायें, खाद्य उत्पादन तथा आधारित धातु उद्योग इत्यादि थे।

— X —